



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 177]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 1, 2005/आषाढ़ 10, 1927

No. 177]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 1, 2005/ASADHA 10, 1927

संस्कृति मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 24 जून, 2005

सं. एफ. 11-3/2004-मिशन.—‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ को संरक्षित और सुरक्षित रखने की आवश्यकता अधिकाधिक महसूस की जा रही है तथा इस पर विश्व स्तर पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के संबंध में एक समझौते की स्वीकृति संबंधी यूनेस्को की पहल, अमूर्त विरासत में बढ़ती जागरूकता एवं रुचि का ही प्रमाण है।

2. देश की समृद्ध ‘अमूर्त सांस्कृतिक विरासत’ के प्रलेखन, अध्ययन और सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पहल की आवश्यकता बहुत पहले से ही महसूस की जा रही है। अनेक संस्थानों और व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में पहले ही उल्लेखनीय कार्य किया है। पहले, इस प्रलेखन को एक राष्ट्रीय डाटाबेस में समेकित किया जाना है।

3. मार्गदर्शी आधार पर परियोजना के रूप में इस कार्य को शुरू करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आई जी एन सी ए) को एक नोडल एजेंसी बनाने का निर्णय लिया गया है। आई जी एन सी ए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगा जिसके आधार पर संस्कृति मंत्रालय उक्त परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

4. यथोचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक ‘परियोजना सलाहकार समिति’ की संरचना की गई है जो निम्नलिखित है :—

(i) सचिव, संस्कृति मंत्रालय	अध्यक्ष
(ii) सदस्य सचिव, आई जी एन सी ए, नई दिल्ली	उपाध्यक्ष एवं परियोजना समन्वयक
(iii) वितीय सलाहकार, संस्कृति मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
(iv) निदेशक, आई जी आर एम एस, भोपाल	वही
(v) निदेशक, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता	वही
(vi) और (vii) दो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के निदेशक	वही
(viii) सचिव, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	वही
(ix) निदेशक, एन.एस.डी., नई दिल्ली	वही
(x) महानिदेशक, सी सी आर टी, नई दिल्ली	वही
(xi) और (xii) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पर दो विशेषज्ञ	वही
(xiii) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय	सदस्य-सचिव

5. गैर-सरकारी सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए, इस निमित्त आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों के लिए लागू निर्धारित दरों/नियमों के अनुसार यात्रा एवं दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

6. प्रारंभ में यह परियोजना दो वर्षों के लिए होगी जिसके बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

के. जयकुमार, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CULTURE

### RESOLUTION

New Delhi, the 24th June, 2005

**No. F. 11-3/2004-Missions.**— The need to preserve and safeguard Intangible Cultural Heritage is being increasingly recognized and discussed the world over. The growing awareness and interest in Intangible Heritage is evidenced by UNESCO's initiative to adopt a convention on the need to safeguard Intangible Cultural Heritage.

2. The need for a national initiative to document, study and safeguard the rich Intangible Cultural Heritage of the country has been felt for a long time. Many institutions and individuals have already done considerable work in this field. In the first instance, this documentation has to be consolidated into a national database.

3. It has been decided to make Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA) the nodal agency to undertake this task as a Project on pilot basis. IGNCA may chalk out a detailed work plan based on which the Ministry of Culture will extend financial support for the Project.

4. To ensure proper coordination, a Project Advisory Committee is constituted as under—

(i) Secretary, Ministry of Culture	Chairperson
(ii) Member Secretary, I.G.N.C.A. New Delhi	Vice-Chairman and Project Coordinator
(iii) Financial Adviser, Ministry of Culture, New Delhi	Member
(iv) Director, I.G.R.M.S., Bhopal	-do-
(v) Director, Anthropological Survey of India, Kolkata	-do-
(vi) & (vii) Directors of two Zonal Cultural Centres	-do-
(viii) Secretary, Sangeet Natak Academy, New Delhi	-do-
(ix) Director, N.S.D., New Delhi	-do-
(x) Director General CCR & T, New Delhi	-do-
(xi) & (xii) Two experts on ICH	-do-
(xiii) Joint Secretary, Ministry of Culture	Member-Secretary

5. Non-official Members will be paid travel and daily allowance for attending the meetings as per prescribed rates/rules applicable to experts for attending such meetings.

6. Initially the Project will be for a period of two years after which it will be evaluated to decide future course of action.

K. JAYAKUMAR, Jt. Secy.